



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 339]
No. 339]नई दिल्ली, बुधवार, मई 28, 1998/ज्येष्ठ 7, 1920
NEW DELHI, THURSDAY, MAY 28, 1998/JYAISTHA 7, 1920

मंत्रिमंडल सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मई, 1998

प्रलेख सं०-160/98

का०आ० 473 (अ):— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग हुए भारत सरकार (कार्य आंबटन) नियम, 1961 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत सरकार (कार्य आंबटन) (दो सौ उनतालीसवां संशोधन) नियम, 1998 है।
(2) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे।
2. भारत सरकार (कार्य आंबटन) नियम, 1961 की,—
(1) प्रथम अनुसूची में,—
(क) "14. गृह मंत्रालय" शीर्ष के अंतर्गत "(iv) गृह विभाग" उप-शीर्ष के पश्चात् निम्नलिखित उप-शीर्ष जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—
"(v) जम्मू-कश्मीर कार्य विभाग";
(ख) "38. जम्मू एवं कश्मीर कार्य विभाग" शीर्ष का लोप किया जाएगा;
(2) द्वितीय अनुसूची में,—
(क) "गृह मंत्रालय" शीर्ष के अंतर्गत "घ. गृह विभाग" उप-शीर्ष और उसके अंतर्गत प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित उप शीर्ष और उससे संबंधित प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी, अर्थात् :—
"ङ जम्मू-कश्मीर कार्य विभाग
1. जम्मू-कश्मीर राज्य की बाबत संविधानिक उपबंध।
2. जम्मू-कश्मीर राज्य से संबंधित सभी अन्य विषय, जिनके अंतर्गत वे विषय नहीं हैं जो विदेश मंत्रालय से संबंधित हैं।"
(ख) "इलेक्ट्रॉनिक विभाग शीर्ष के पश्चात् आने वाला "जम्मू एवं कश्मीर कार्य विभाग" शीर्ष और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।"

के० आर० नारायणन,
राष्ट्रपति[फा. सं. 1/22/1/98-मंत्रि०]
बी०के० गाबा, अवर सचिव

**CABINET SECRETARIAT
NOTIFICATION**

New Delhi, the 27th May, 1998

Doc. CD-160/98.

S.O. 473 (E).— In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely :—

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) (Two hundred and Thirtiyninth Amendment) Rules, 1998.

(2) They shall come into force at once.

2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961,—

(1) in the First Schedule,—

(a) under the heading “14. Ministry of Home Affairs (Grih Mantralaya)”, after the sub-heading “(iv) Department of Home (Grih Vibhag)”, the following sub-heading shall be added, namely:—

“(v) Department of Jammu and Kashmir Affairs (Jammu tatha Kashmir Vibhag)”;

(b) the heading “38. Department of Jammu and Kashmir Affairs (Jammu tatha Kashmir Vibhag)” shall be omitted;

(2) in the Second Schedule,—

(a) under the heading “Ministry of Home Affairs (Grih Mantralaya)”, after sub-heading “D. Department of Home (Grih Vibhag)” and the entries thereunder, the following sub-heading and the entries relating thereto shall be added, namely:—

“E. Department of Jammu and Kashmir Affairs (Jammu tatha Kashmir Vibhag)

1. Constitutional provisions with respect to the State of Jammu and Kashmir.

2. All other matters relating to the State of Jammu and Kashmir excluding those with which the Ministry of External Affairs (Videsh Mantralaya) is concerned.”;

(b) the heading “Department of Jammu and Kashmir Affairs (Jammu tatha Kashmir Vibhag)” and the entries relating thereto appearing after the heading “Department of Electronics (Electroniki Vibhag) shall be omitted.”.

K.R. NARAYANAN,
PRESIDENT

[File No. 1/22/1/98-Cab.]

V.K. GAUBA, Under Secy.